

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [इलाहाबाद उच्च न्यायालय](#) के न्यायाधीश के विवादित बयान के बाद उन्हें पद से हटाने के लिये 55 सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित [महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा](#) में पेश किया गया है।

मुख्य बिंदु

- **मुद्दे के बारे में:**
 - न्यायाधीश ने वगित वर्ष दिसंबर में [वशिव हद्दि परषिद](#) के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कुछ सांप्रदायिक टिप्पणियों की थीं।
 - राज्यसभा में वपिक्ष के 55 सांसदों ने [न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968](#) के तहत न्यायाधीश को उनके कथित कदाचार के लिये न्यायाधीश के पद से हटाने के लिये प्रस्ताव पेश करने हेतु नोटिस दिया है।
- **न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:**
 - [अनुच्छेद 124 और 218](#) के तहत, [सर्वोच्च न्यायालय](#) और [उच्च न्यायालयों](#) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा “सद्धि दुरव्यवहार” या “अक्षमता” के आधार पर हटाया जा सकता है।
 - हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है:
 - सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
 - उसी सत्र में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तहाई का [वशेष बहुमत](#)।
 - संविधान में “सद्धि कदाचार” और “अक्षमता” शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार [दुरव्यवहार](#) में [जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, नषिटा की कमी](#) या [नैतिक अधमता](#) शामिल है।
 - [अक्षमता](#) से तात्पर्य न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली शारीरिक या मानसिक स्थिति से है।
- **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रक्रिया:**
- **प्रस्ताव की सूचना:**
 - इसके लिये कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों या 100 [लोकसभा](#) सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
 - परामर्श के बाद अध्यक्ष या [स्पीकर](#) यह नरिणय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं।
- **गठित जाँच समिति:**
 - यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित [तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है](#)।
 - समिति आरोपों की जाँच करती है:
 - यदि [न्यायाधीश को दोषमुक्त कर दिया जाता है](#), तो प्रस्ताव नरिसत हो जाता है।
 - यदि [दोषी पाया जाता है तो समितिकी रपिर्ट मतदान के लिये संसद](#) में भेजी जाती है।
- **संसदीय अनुमोदन:**
 - [राष्ट्रपति](#) द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिये [दोनों सदनों को वशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा](#)।